राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 31 | अंक 8-9 | अगस्त-सितम्बर 2010 | नई दिल्ली | मूल्य 5 रु. | पृष्ठ 32

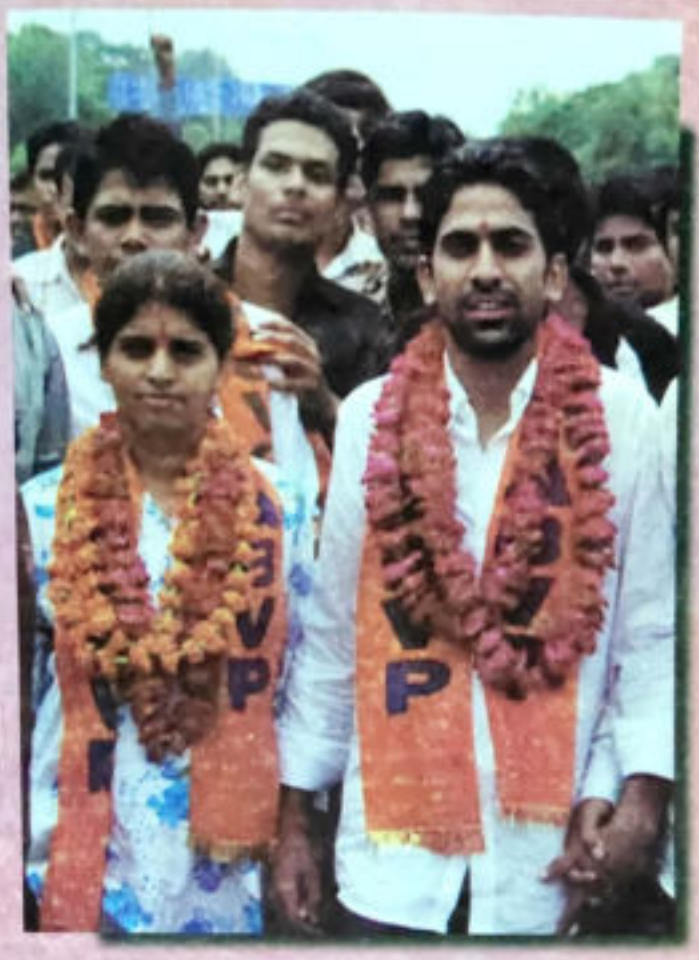

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विजयी प्रत्याशी जितेन्द्र चौधरी डूसू अध्यक्ष (मध्य में), प्रिया डबास, डूसू उपाध्यक्ष (दाएं) तथा नीतू डबास, डूसू महासचिव (बाएं)

राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मनीष यादव व उपाध्यक्ष मीनाक्षी मीणा

विजय का शंखनाद

दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी व कार्यकर्ता

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में मुम्बई में आयोजित रैली में व्यापारीकरण के खिलाफ संकल्प लेते राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय मंत्री रवि कुमार, प्रांत मंत्री अमोल पाटिल व छात्र समुदाय

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में राजभवन घेराव कार्यक्रम में बंगलौर में सभा को सम्बोधित करते पी.वी. कृष्ण भट्ट व उपस्थित कार्यकर्ता

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011-43098248
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट कैम्पस, यूनिवर्सिटी एरिया, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.30 नवीन शहादरा, दिल्ली. 32 द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
सम्पादकीय : विजय का यह पर्व		4
अभाविप का विजय अभियान		6
सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा	-सुनील आंबेकर	8
'शिक्षा का व्यापारीकरण बर्दाश्त नहीं'		9
भारतीय संसाधनों पर विदेशी हितपूर्ति	-देवेन्द्र शर्मा	11
मजहब के बहाने शिक्षा का कारोबार		14
किशनगंज में ए.एम.यू. की शाखा होगी आतंकवाद...		16
यह स्वायत्तता नहीं गले की फांस है	-अजय भारती	17
पं. दीनदयाल उपाध्याय : समर्पित जीवन		19
दस्तावेज : त्रिमूर्ति पद छोड़े		21
हिन्दी की शताब्दियां	-आशुतोष	22
असम विश्वविद्यालय पर अभाविप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन		24
पटना में पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन		25
मेरठ में मोटर साइकिल रैली		27
प्रान्तीय छात्र नेता सम्मेलन सम्पन्न		28
एबीवीपी ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन		29

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

विजय का यह पर्व

जुलाई-अगस्त के महीने में जहां विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी गतिविधियां चलती हैं वहीं सितम्बर का महीना सामान्य रूप से छात्रसंघ चुनावों और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहता है। इन्हीं दिनों में शिक्षकों और कर्मचारियों के संगठनों के चुनाव और हड़तालों का आयोजन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद परिसरों में विधिवत शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है और परिसर खबरों से बाहर हो जाते हैं।

समाचार जगत की दृष्टि में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के परिसरों से इसके बाद समाचारों की संभावना कम हो जाती है। प्रथमदृष्ट्या तो इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आती किन्तु गहराई से विश्लेषण करें तो इसके निहितार्थ चिंतित करने वाले हैं।

परिसरों की खामोशी शासन-प्रशासन के लिए तो सुविधाजनक हो सकती है लेकिन शिक्षा अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भारत जैसे देश में जहां समस्याओं का अंबार लगा है, परिसरों से समाचार न निकलने का अर्थ है विद्यार्थियों की इनके प्रति अवहेलना। शिक्षा के सामने उत्पन्न समस्याओं तथा राष्ट्र के समक्ष खड़ी चुनौतियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला विद्यार्थी इस बात का द्योतक है कि परिसर अपनी जीवंतता खो चुके हैं।

कल्पना करें कि आज से सौ साल पहले भी परिसर इतने मूक और असंपृक्त रहे होते तो क्या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा सकती थी? शायद नहीं! स्वतंत्रता पाने के लिए जिस छात्रशक्ति की आवश्यकता गांधी से लेकर भगत सिंह तक ने अनुभव की, स्वतंत्रता के पश्चात उसे बनाये रखने के लिए उसकी वह भूमिका और राष्ट्र पुनर्निर्माण में उसकी भागीदारी को क्यों नकार दिया गया? अगर देश का छात्र-युवा इस समूची प्रक्रिया से बाहर रहा तो क्या सरकारी भोंपुओं से भारत निर्माण का राग अलापने से सचमुच बात बनने वाली है?

विडंबना यह है कि समाज का हर वह वर्ग जो किसी न किसी रूप में व्यवस्था से जुड़ा है, नहीं चाहता कि बुनियादी प्रश्नों पर छात्र-युवा एकजुट हों, नेतृत्व संभालें, प्रश्न खड़े करें। व्यवस्था की नीति और नियत पर उठने वाले असुविधाजनक प्रश्नों को टालने के लिए वे छात्र नेतृत्व का ही गला घोंट देना चाहते हैं। यही कारण है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये ही नहीं जाते। जहां वे होते भी हैं वहां प्रशासन का आग्रह अप्रत्यक्ष चुनाव अथवा मनोनयन पर रहता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी चुनावों पर इतने बंधन लाद दिये गये हैं कि कुछ ही समय में छात्रसंघ चुनाव महज कर्म-कांड बन कर रह जायेंगे। जवाहर लाल नेहरू

विश्वविद्यालय में तो छात्र-संघ चुनाव की एक अनूठी ही पद्धति है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर न्यायालय की मुहर ने जेएनयू में परंपरागत रूप में छात्रसंघ चुनावों की संभावना ही समाप्त कर दी है ।

हैरत की बात है कि यह सारे नियम कायदे केवल छात्रसंघ के चुनाव पर ही लागू होते हैं। उन्हीं परिसरों में होने वाले शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों के चुनाव पर ऐसे कोई नियम नहीं लागू होते। छात्रसंघ का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उपस्थिति कम होने पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है लेकिन शिक्षक नेता बिना कक्षाएं पढ़ाये अथवा कर्मचारी नेता बिना काम किये चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं।

गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव परिणाम प्रोवीजनल घोषित किये गये और पूरा वर्ष बीतने पर भी उन्हें नियमित नहीं किया गया। निर्वाचित पदाधिकारियों पर निर्वाचन अयोग्य घोषित किये जाने की तलवार साल भर लटकी रही। इस वर्ष पुनः इसे दोहराया गया है। सभी विजयी प्रत्याशियों का निर्वाचन प्रोवीजनल घोषित किया गया है। यह अपने-आप में एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग है जो छात्र राजनीति के लिये शुभ संकेत नहीं है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी रचनात्मक छात्र आन्दोलन का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। छात्र-युवाओं की हुंकार पर तानाशाही सत्ता को भूमिसात् होते हुए देश ने देखा है। आज एक बार पुनः वे ही परिस्थितियां उत्पन्न होती दिख रही हैं। सरकारें देश की संप्रभुता की कीमत पर समझौते कर रही हैं। छात्र नेतृत्व को कमजोर करने के कुचक्रों को संवैधानिक जामा पहनाया जा रहा है।

उपरोक्त कृत्य चोरी-छिपे नहीं किये जा रहे हैं। देश का आम छात्र भी इन स्थितियों को समझ रहा है। इसका प्रमाण है कांग्रेस सल्तनत के युवराज के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने संबंधी बयानबाजी को नकार कर छात्रों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिया गया भारी समर्थन। उत्तराखण्ड से लेकर राजस्थान तक इस वर्ष जहां भी छात्र संघ चुनाव हुए, विद्यार्थी परिषद की विजय पताका लहरायी है। दिल्ली में जहां युवराज स्वयं नजर रखे थे वहीं हिमाचल प्रदेश में भी वे दौरे पर गये थे। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कोई भी प्रत्याशी सौ वोट तक नहीं पा सका।

यह परिणाम वर्तमान अव्यवस्था के विरुद्ध क्षोभ की अभिव्यक्ति हैं। परिषद के पक्ष में छात्रों ने जो समर्थन व्यक्त किया है वह संगठन को जिम्मेदारियों से बांधता है। अनेक वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ से बाहर रहने के बाद भी परिषद की निरंतर सक्रियता का ही परिणाम है कि संगठन को इतनी शानदार जीत हासिल हुई है।

परिसर को स्पंदनयुक्त और जीवंत बनाने तथा राष्ट्रीय प्रश्नों पर छात्रशक्ति को जागृत करने, परिसरों में शैक्षिक वातावरण की बहाली और शुचिता के संरक्षण के लिये होने वाले रचनात्मक संघर्ष में विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करना किसी भी जिम्मेदार छात्र संगठन की स्वाभाविक भूमिका है। अभाविप विद्यार्थियों के इस विश्वास पर खरी साबित होगी और अपने इस उत्तरदायित्व का यशस्वी निर्वहन करेगी, विजय के इस पर्व पर आज यह विश्वास दिलाते हुए छात्रशक्ति परिवार अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। ■

अभाविप का विजय अभियान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाल ही में सम्पन्न हुए 'दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों' में शानदार वापसी करते हुए दिल्ली की छात्र राजनीति में एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। इस वर्ष अभाविप के उम्मीदवारों ने 'दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ' की चार सीटों में से तीन सीटों पर वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर छात्र राजनीति में अभाविप के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी संगठन एनएसयूआई को इस बार एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। तीन सीटों पर अभाविप के उम्मीदवारों ने एनएसयूआई के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त दी।

जितेन्द्र चौधरी ने अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल 10 अन्य उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, और 1943 वोटों की बढ़त के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। उनके खाते में कुल 9259 वोट पड़े। वहीं एनएसयूआई के हरीश चौधरी को 7316 वोटों के साथ हार का स्वाद चखना पड़ा। उपाध्यक्ष पद के लिए प्रिया डबास को भी 1518 मतों की बढ़त के साथ विजयी घोषित किया गया। उपाध्यक्ष पद पर प्रिया डबास के प्रतिद्वंद्वी रहे एनएसयूआई के वर्धन चौधरी को कुल 7161 वोट ही प्राप्त हो पाए। लेकिन इस सब के बीच अभाविप की नीतू डबास ने एनएसयूआई की प्रत्याशी दीपिका देशवाल को 4495 वोटों के भारी अंतर से हराया। उनके खाते में कुल 9197 वोट पड़े। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई ने अपना कब्जा बरकरार रखा और एनएसयूआई के उम्मीदवार अक्षय कुमार ने 632 मतों के मामूली अंतर से अभाविप के सौरभ उनियाल को हराया।

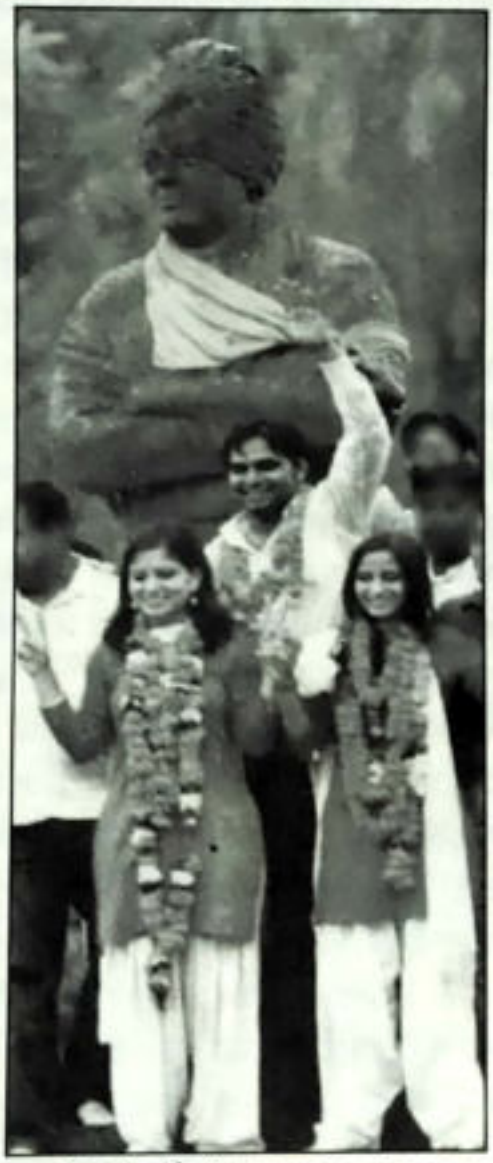

मध्य में जितेन्द्र चौधरी (अध्यक्ष), बाएं उपाध्यक्ष प्रिया डबास तथा दाएं सचिव नीतू डबास

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विजेता उम्मीदवारों ने अपनी जीत पर छात्रों का आभार प्रकट करते हुए अपनी जीत को राष्ट्रवाद की जीत करार दिया है। उन्होंने इस जीत को अपनी जीत न कहकर छात्रों की जीत कहा और छात्रों के हित की लड़ाई लड़ने की बात दोहराई। अध्यक्ष पद पर जीतने वाले जितेन्द्र चौधरी ने कहा कि लंबे समय से छात्र एक आंदोलन की जरूरत महसूस कर रहे थे, एबीवीपी की जीत उसी जरूरत का परिणाम है। उन्होंने चुनाव के समय किए वादों को पूरा करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि सेमेस्टर सिस्टम को हटाने और कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से हॉस्टल से बाहर हुए छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।

उपाध्यक्ष पद पर विजयी उम्मीदवार प्रिया डबास ने कहा कि उनके और उनके संगठन की तरफ से शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में आए दिन छात्राओं के साथ सुरक्षा को लेकर परेशानियां आती रहती हैं। उनकी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपनी जीत को संगठन की जीत बताया।

वहीं सचिव पद पर चुनी गई

नीतू डबास ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जिस तरह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार की तमाम बातें सामने आईं, उसका परिणाम छात्रों ने एबीवीपी को बहुमत देकर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे और कॉलेजों में छात्रों के समक्ष समस्याएं न आएं ऐसा प्रयास करेंगे।

हालांकि इस वर्ष अन्य वर्षों के मुकाबले वोटिंग में छात्रों की संख्या काफी कम रही। लेकिन इस कमी का कारण छात्रों का वोटिंग में रूझान कम होना नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की चल रही हड़ताल को माना जा रहा है। डीयू में सेमेस्टिर सिस्टम लागू हो चुका है किन्तु शिक्षकों और डीयू प्रशासन में इस बात को लेकर ठनी हुई है। कुछ कारणों से शिक्षक अभी छात्रों को सेमिस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। जिससे महीने भर से छात्रों की पढ़ाई ठप्प पड़ी हुई है। इससे कॉलेजों में छात्र सक्रिय नहीं हैं, जो कम वोटिंग का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, कम वोटिंग में रही-सही कसर दिल्ली की बारिश ने पूरी कर दी। दूसरी पाली के मतदान के ठीक पहले राजधानी में हुई झमाझम वर्षा ने वोटिंग प्रतिशत को धो कर रख दिया।

उधर दूसरी ओर कुछ मीडिया और राजनीति के मिले-जुले विवेचन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभाविप की इस जीत में कांग्रेस सरकार द्वारा दिल्ली में होने वाले राष्ट्रकुल खेलों में हो रही अनियमिताएं और घोटाले हैं। वहीं अभाविप संगठन के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत अभाविप के कार्यकर्ताओं की छात्रों के बीच सक्रियता का प्रमाण है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में प्रभावी पद पर न रहते हुए भी वर्ष भर छात्रों के बीच में सक्रिय रहे, छात्रों को होने वाली कठिनाईयों से अभाविप के छात्र-कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका सामना किया। जिसके बाद छात्रों ने ऐसा महसूस किया कि अभाविप राजनीति के लिए नहीं बल्कि छात्रशक्ति को आधार बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला संगठन है। जिसके फलस्वरूप अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में यह सफलता हासिल की है।

अभाविप के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर संगठन को सात साल बाद जीत हासिल हो पाई है। इस जीत से संगठन ने छात्रों के बीच अपनी खोई हुई साख को एक बार फिर हासिल किया है। 2003 के बाद से अभाविप दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी बार दो से अधिक सीटें नहीं जीत पाई थी। लेकिन एबीवीपी ने तब से लेकर अब तक प्रभावी स्तर पर छात्र संघ में न रहते हुए भी अपनी छवि छात्रों के बीच उनके हितैषी के तौर पर बरकरार रखी और इन सात सालों के दौरान एबीवीपी ने जरूरत पड़ने पर छात्र संघ में न रहते हुए भी शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिए कई आन्दोलन चलाए जिसका परिणाम आज इस जीत के रूप में सामने आया है।

मनीष यादव

उधर राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद ने विजय का शंखनाद किया। अभाविप के प्रत्याशी मनीष यादव अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। उन्होंने एनएसयूआई के मुकेश भाकर को 177 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी मिनाक्षी मीणा ने 250 मतों से एनएसयूआई की चन्द्रकांता मीणा को पराजित किया।

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में अभाविप के रायसिंह चौधरी अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 74 मतों से पराजित किया।

इस शैक्षणिक सत्र में जीत की शुरूआत राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू हुई जिस क्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब, गुजरात में छात्र संघ चुनाव में विजय का डंका बजाया। ■

सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा

-सुनील आंबेकर
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप

मैं छत्तीसगढ़ के चांपा में 17 सितम्बर, 2010 को प्रवास पर था। स्वाभाविक है कि कई छात्रों से मिला। बाद में दोपहर बाद जांजगीर व बिलासपुर गया था। शिक्षा के व्यापारीकरण एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अभाविप द्वारा देशव्यापी चक्का जाम (16 सितम्बर) के संदर्भ में चर्चा कर रहा था। 11वीं-12वीं और स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत कार्यकर्ता बता रहे थे कि उन्हें महाविद्यालय बंद एवं चक्का जाम में छात्र-शिक्षक समेत सामान्य लोगों का अत्यधिक समर्थन था। कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। बल्कि बढ़-चढ़कर ऐसा विषय उठाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था। सभी से प्रोत्साहन मिल रहा था।

यह कहानी केवल चांपा या बिलासपुर की नहीं अपितु देश के हर कोने से इस तरह की घटनाएं मेरे पास आ रही है। विद्यार्थी परिषद् की यह मांग कि शिक्षा सस्ती हो व सभी के लिए उपलब्ध हो, सामान्य लोगों के मन को छू रही है। हमारे देशवासी भारत को महाशक्ति बनाने का सपना देख रहे हैं। वे 21वीं सदी में भारत को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत तथा सभी प्रकार से प्रगतिशील स्वरूप में देश को देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहे महानगर का हो या गांव का, स्वयं भी इस प्रगति का हिस्सा बनना चाहता है। हर समुदाय में निराशा को त्यागकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा जगी है। स्वाभाविक ही हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको जीवन में सफल बनाना चाहता है। ऐसे मौके पर शिक्षा की उचित, सर्वव्यापी व सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की जगह केन्द्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र से हाथ खींचकर शिक्षा को बाजार के हवाले कर रही हैं। लोगों की बढ़ती मांग व स्पर्धा को देखते हुए बाजारू तत्वों ने इसे महंगा बना दिया है तथा सामान्य लोगों की पहुंच से यह दूर हो रही है। महंगी शिक्षा कई परिवारों के सपनों और उनके बच्चों के भविष्य को निराशा में धकेल रही है। कई गरीब परिवारों के लोग परिस्थिति की विवशता समझकर निराशा में अपने हाथ खींचकर बच्चों को समझा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व एक बैंक में डकैत पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वह पेशेवर गुनहगार नहीं अपितु अपनी पुत्री की इंजीनियरिंग की फीस के मात्र बीस हजार रुपए निश्चित समय सीमा में भरने हेतु इस कृत्य के लिए मजबूर हुआ। वस्तु स्थिति का आभास होने पर संवेदना जगी तो पुलिस और बैंक के लोगों ने उसकी बेटी की फीस भरने की व्यवस्था की। परन्तु पता नहीं कितने लोगों ने ऐसी परिस्थिति का सामना किया होगा व कितने भविष्य बर्बाद हुए होंगे। इस दर्द ने ही विद्यार्थी परिषद् के शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने हेतु चल रहे आंदोलन को जन्म दिया है। यह आन्दोलन प्रभावी बनेगा व निर्णायक भी होगा।

केन्द्र सरकार को इस संदर्भ में एक समग्र व प्रभावी केन्द्रीय कानून बनाना ही होगा। साथ में राज्य सरकारों को नई व्यवस्था को लागू करने हेतु उचित प्रावधानों के साथ नए पूरक कानून भी बनाने होंगे। यही समय की मांग है।

वैश्वीकरण का यह सिद्धांत कि बाजारवाद सभी को दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध वस्तु एवं सेवाओं तक पहुंचने का अवसर देकर न्यायपूर्ण एवं साफ-सुथरी व्यवस्था देता है तथा निजीकरण इसमें सर्वाधिक उचित माध्यम है, लेकिन वर्तमान अनुभव इन धारणाओं को बाकी सभी क्षेत्रों में गलत साबित कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों को देखते हुए बिना न्यायपूर्ण प्रावधानों के केवल निजीकरण से शिक्षा का विस्तार होने पर सभी को शिक्षा का अवसर मिलेगा, यह मानना बेमानी होगा। इसलिए 'सभी को शिक्षा-सस्ती शिक्षा' की गारंटी देने वाली व्यवस्था दे सके ऐसा कानून देश में लागू कराना नितांत जरूरी है।

■

'शिक्षा का व्यापारीकरण बर्दाश्त नहीं'

लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय छात्रनेता सम्मेलन में शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध आह्वान

राष्ट्रीय छात्र नेता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी

शिक्षा का व्यापारीकरण यह सिर्फ छात्रों का नहीं तो समस्त समाज का विषय है, इसके विरोध में समाज ने खड़ा होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय छात्र नेता सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए रा.स्व.संघ के सरकार्यवाह श्री सुरेश जोशी ने व्यक्त किए। 'शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा अर्थ से जुड़ने के बाद उसमें अनर्थ हो जाता है' ऐसा बताते हुए उन्होंने कहा 'पूर्व में हमारे यहां शिक्षा से आय कमाने की कल्पना नहीं थी।'

निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू न करते हुए सरकार सामाजिक अन्याय कर रही है साथ ही निजी संस्थानों पर नियंत्रण का दायित्व सरकार का ही है यह उनको बताना पड़ेगा। शिक्षा के व्यापारीकरण के इस आंदोलन के माध्यम से आप लोगों के मन की पीड़ा, सामान्य छात्र के अंत:करण की भावना को व्यक्त कर रहे हैं इसलिए अभाविप का अभिनन्दन है। समाज असंगठित होने के कारण विरोध नहीं करता लेकिन आप यह कर सकते हैं।

इसके पूर्व प्रात: उद्घाटन सत्र में लखनऊ के महापौर डॉ. दिनेश शर्मा, अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा मध्य उत्तर प्रदेश प्रान्त के अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश की उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र का संचालन कु. अश्विनी परांजपे (राष्ट्रीय मंत्री) ने किया। उद्घाटन करते हुए डा. दिनेश शर्मा ने कहा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण पश्चिमी संस्कृति की नकल है। भारतीय शिक्षा प्रणाली सदा से ही गुणवत्तापूर्ण तथा सम्पन्न रही है, जिसके उदाहरण नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय है। पहले देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए महिला अपने गहने गिरवी रखती थी परंतु शिक्षा के व्यापारीकरण के चलते अब बच्चों के

पढ़ाने के लिए उन्हें गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि 'राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम' के जरिये सरकार किसानों की तरह छात्रों को भी आत्महत्या के रास्ते पर धकेल रही है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल नये-नये बिलों के द्वारा सुधारों के नाम पर निजीकरण तथा व्यावसायीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस तथा डोनेशन था लेकिन आज के.जी. से पी.जी. तक सभी प्रकार की शिक्षा में व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। इसके चलते गरीब तथा मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके खिलाफ लम्बे संघर्ष के लिए तैयार होने का आह्वान उन्होंने सभी छात्र नेताओं से किया।

सम्मेलन के एक सत्र में राष्ट्रीय मंत्री श्री रवि कुमार ने अभाविप द्वारा चल रहे देशव्यापी शुल्क सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट सबके सम्मुख रखी। देशभर के शासकीय महाविद्यालयों में एक ही कोर्स की फीस में बड़ी असमानता है ऐसा बताते हुए उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया जहां शासकीय महाविद्यालय में अभियांत्रिकी के लिए महज रु. 2250/- शुल्क है तो वहीं पंजाब में रु. 82,000/- है। सभी व्यावसायिक कोर्सेस के लिए निजी महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर डोनेशन लिये जाने की बात भी सामने आयी है। निजी महाविद्यालय विविध मदों पर दंडात्मक शुल्क लगाकर छात्रों का शोषण कर रहे है यह भी उजागर हुआ।

विविध प्रांतों से आये हुए छात्र नेताओं ने अपने प्रांत में उच्च शिक्षा की स्थिति तथा व्यापारीकरण के हो रहे प्रभाव से सबको अवगत कराया। राष्ट्रीय मंत्री श्री उमेशदत्त द्वारा इस विषय पर रखे गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दिनभर चले इस सम्मेलन में 24 प्रांतों के 123 छात्र नेता उपस्थित रहे। ■

अनिकेत काले 'WOSY' महासचिव

'WOSY' की अंतरराष्ट्रीय बैठक हैदराबाद में 22 अगस्त, 2010 को सम्पन्न हुई जिसमें औपचारिक रूप से अनिकेत काले को 'WOSY' का महासचिव घोषित किया गया। अनिकेत काले ने पुणे विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. किया है। 'WOSY' के पुणे चैप्टर के लिए पिछले 5 वर्षों से वो कार्यरत रहे हैं।

डॉ. चेत्रा जो 'WOSY' के अब तक महासचिव थे इस दायित्व पर रहते हुए वे अपने शोध कार्यों के साथ न्याय न कर पाने के कारण उन्होंने इस दायित्व से मुक्त रहकर काम करने की इच्छा दर्शायी। इसके पश्चात एक बैठक में अनिकेत काले को महासचिव के रूप में घोषित किया गया। ■

करीमगंज में भी अभाविप विजयी

20 अगस्त, 2010 को रवीन्द्र सदन महिला महाविद्यालय में अभाविप ने इतिहास रचा। महाविद्यालय छात्रसंघ के लिए हुए चुनावों में महासचिव पद पर प्रियंका दत्ता, 37 मतों से, एवं सचिव पद पर अनुराधा दास 33 मतों से विजयी रही हैं। इस महाविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में प्रधानाध्यापक को माना जाता है। अभाविप का पूरा पैनल जीत कर आया। और उसने छात्रसंघ का गठन किया। अभाविप इस महाविद्यालय में लगातार जीतती आ रही है। इस बार की कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर अभाविप ने पुनः अपना परचम लहरा दिया है। इस महाविद्यालय में उपाध्यक्ष के लिए सभी दलों के नामांकन रद्द हो गए थे। ■

मजहब के बहाने शिक्षा का कारोबार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित संत थॉमस स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें ईसाई बच्चे 50 से भी कम हैं। इसी तरह दिल्ली के पास खतौली में कोई कैथोलिक परिवार ही नहीं है, पर कान्वेंट चल रहा है। प्रश्न खड़ा होता है कि जहां स्कूल में बच्चे ईसाई नहीं, अध्यापक ईसाई नहीं, तो चर्च किस धर्म, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक-अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार का पूरा तंत्र चर्च को खुश करने में लगा है। चाहे उसके ऐसे फैसलों से ईसाई समुदाय के एक बड़े वर्ग को ही दुख उठाने पड़ रहे हों।

हाल ही में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने चर्च के शिक्षा संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय सुनाया है कि अल्पसंख्यक की मान्यता देने या छीनने में अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या कोई आधार नहीं होगी। ये चाहे कितने भी गैर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को दाखिला दे दें, तो भी इनका अल्पसंख्यक का दर्जा और उस आधार पर मिलने वाली सभी छूटें बरकरार रहेंगी। यह निर्णय आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक पूर्व-निर्णय के विपरीत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को दाखिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का एक निश्चित सीमा तक ख्याल रखना होगा।

इसी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की सहूलियत के लिए नवम्बर-2004 में एनसीएमईआई का गठन पूर्व न्यायाधीश एमएसए सिद्दीकी की अध्यक्षता में किया था। अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत अपनी इच्छा से अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की छूट दी गई है। इसी के तहत मुस्लिम, सिख व ईसाई बड़ी संख्या में अपने संस्थान चला रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए खास अधिकारों का मकसद अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति व धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, पर भारतीय चर्च ने देश की स्वतंत्रता के बाद इस अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया हैं। उन्होंने इसे अपने विस्तार का जरिया बना लिया है।

मुस्लिम और सिख समुदाय की ओर से अपने संस्थानों में दाखिला न मिलने की शिकायतें कम ही मिलती हैं। समस्या चर्च से जुड़े संस्थानों के साथ है। देशभर में चर्च ने शिक्षा संस्थानों का जाल बिछा दिया है। देश की कुल आबादी के ढाई प्रतिशत ईसाई समुदाय का देश की 22 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं पर एकाधिकार है, पर इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में 15 व ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत ईसाई बच्चे निरक्षर हैं। चर्च द्वारा संचालित कान्वेंट स्कूलों में गरीब ईसाई बच्चों को दाखिला ही नहीं दिया जाता। यानी, संविधान में मिले खास अधिकारों का लाभ धन कमाने और चर्च के विस्तार में किया जा रहा है। अगर चर्च ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई होती, तो आजादी के 63 वर्ष बाद उसे अपने अनुयायियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की दुहाइयां नहीं देनी पड़ रही होतीं।

एनसीएमईआई के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थीं, जिन्हें देखते हुए आयोग के अध्यक्ष को कहना पड़ा है कि मुस्लिम व सिख समुदायों के शिक्षा संस्थान अपने बच्चों को ज्यादा लाभ दे रहे हैं। समस्या केवल चर्च द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों के साथ है। अत: अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग प्रस्ताव पास करता है कि जो ईसाई शिक्षा संस्थान अपने समुदाय के बच्चों को 30 प्रतिशत भागीदारी नहीं देगा, वह अल्पसंख्यक का दर्जा खो देगा। एनसीएमईआई के इस निर्णय के विरुद्ध भारतीय चर्च ने मोर्चा खोल दिया है। कैथोलिक बिशप कान्फ्रेंस ऑफ इंडिया के शिक्षा एवं

संस्कृति आयोग ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष आयोग द्वारा चर्च के शिक्षा संस्थानों में ईसाई बच्चों की देखभाल सीमा तय करने पर एतराज जताया है। प्रधानमंत्री भी चर्च के सामने झुक गए लगते हैं। यानी, उन्हें ईसाइयों की नहीं, चर्च की चिंता है।

बिशप कान्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद-30(1) में उन्हें अपने शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है और संविधान में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा पाने के लिए छात्रों का कोई प्रतिशत तय नहीं किया गया है। हमारी आबादी भी कम है, इसलिए हम इस निर्णय की निंदा करते हैं। इसके बाद आयोग अपने इस आदेश को बदलने की तरकीब ढूंढ रहा था, जो उसे उड़ीसा सरकार बनाम एक चर्च-स्कूल के बीच उठे विवाद पर आए अदालत के फैसले ने सुझा भी दी है। उड़ीसा सरकार ने एक स्कूल पर आरोप लगाया था कि उसमें ईसाई बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए स्कूल का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त होना चाहिए। मामला एक निचली अदालत में गया, तो फैसला स्कूल के पक्ष में आया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग अब इसी के आधार पर अपने पुराने फैसले से मुकर गया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता जोजफ गाथिया मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने का संवैधानिक अधिकार कुछ जिम्मेदारियों के साथ दिया गया था, ताकि ऐसे संस्थानों के जरिए समुदाय के पिछड़े एवं गरीब सदस्यों को अन्य वर्गों की बराबरी के साथ विकास के मौके उपलब्ध हो सकें। इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो, इसलिए कुछ जायज प्रतिबंध लगाना गैर-संवैधानिक नहीं है। मसलन-इन स्कूलों-संस्थानों में अल्पसंख्यक बच्चों को दाखिला न देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। गाथिया प्रश्न करते हैं कि संविधान में मिले अधिकारों के तहत चर्च अपने शिक्षा संस्थान किसके लिए चलाना चाहता है? एनसीएमईआई द्वारा सुनाए गए फैसले पर कैथोलिक बिशप कान्फ्रेंस ऑफ इंडिया के शिक्षा एवं संस्कृति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री के सामने यह तर्क देना कि संविधान में प्रतिशत तय नहीं किया गया है, क्या स्वीकार करने योग्य है? क्या इसे इस बात की गारंटी मान लिया जाए कि यदि आप अल्पसंख्यक हैं, तो आप अल्पसंख्यक अधिकारों के तहत अपनी मर्जी से कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपने शिक्षा संस्थान देश के कोने-कोने में खोलें और जितना चाहें, धन कमाएं?

देशभर में चर्च हजारों कान्वेंट स्कूल चला रहा है। ये सभी स्कूल ईसाई समुदाय की भाषा, संस्कृति आदि की रक्षा की खातिर चलाए जा रहे हैं, बाकायदा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा पाकर, पर क्या कभी सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि इन स्कूलों में ईसाई समुदाय के छात्रों का प्रतिशत कितना है? इन स्कूलों में अधिकतर छात्र दूसरे समुदायों के होते हैं, तो फिर उनके बीच ईसाई धर्म-संस्कृति का प्रचार कैसे होता होगा? कुल मिलाकर भारतीय संविधान में दिये गए अधिकार का केवल दुरुपयोग ही किया जा रहा है। संविधान का मकसद अल्पसंख्यकों का विकास करना था, न कि उनके नाम पर शिक्षा के व्यापार को संरक्षण देते रहना। ■ **आर.एल. फ्रांसिस**

(राज एक्सप्रेस दैनिक से साभार)

कश्मीर स्वायत्तता पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर कश्मीर को स्वायत्तता देने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। दोपहर 2 बजे के आसपास अभाविप के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर एकत्र हुए और कश्मीर के बारे में केन्द्र के नरम रवैये की जमकर आलोचना की। जितेन्द्र चौधरी, प्रिया डबास, सौरभ उनियाल, ललित चौधरी, जयराम आदि छात्र नेताओं के भाषण हुए। रैली निकालने के बाद राष्ट्रीय मंत्री श्री श्रीरंग कुलकर्णी, दिल्ली प्रदेश मंत्री श्री आशुतोष श्रीवास्तव तथा राष्ट्रीय राजधानी कार्यालय मंत्री श्री आलोक पांडे ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर उन्हें सम्बोधित कर ज्ञापन सौंपा। ■

किशनगंज में ए.एम.यू. की शाखा होगी आतंकवाद की पाठशाला

पटना, 31 जुलाई 2010 : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में खोलने के विरोध में स्थानीय कारगिल चौक पर महाधरना का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने 'बिहार की धरती पर आतंकी पाठशाला ए.एम.यू. की शाखा नहीं खुलेगी, केन्द्र सरकार एवं नीतीश सरकार शर्म करो ए.एम.यू. की शाखा बंद करो, केन्द्र सरकार एवं नीतीश सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण बन्द करो, ए.एम.यू. धोखा है छात्रों देश बचाओ मौका है, आदि गगनभेदी नारे लगा रहे थे।

इस अवसर पर अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राम नरेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके नीतिश कुमार ने ए.एम.यू. की शाखा किशनगंज में खोलने एवं 250 एकड़ भूमि मुफ्त आवंटित करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन किया है। अभी माननीय केरल उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में ए.एम.यू. की शाखा खोलने पर रोक लगाकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मंसूबे की कलई खोल दी है। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है इसलिए अभाविप नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करती है। विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुमार ने कहा कि तमाम राजनेता मुस्लिम वोट-बैंक के लालच एवं तुष्टिकरण की दलदल में फंस चुके हैं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। सभी पार्टी के नेताओं में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में खोलने के निर्णय का श्रेय लेने की होड़ मची है। वे ए.एम.यू. की शाखा के माध्यम से किशनगंज जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिले में आतंकवाद की पाठशाला खोलने का समर्थन कर रहीं है। विद्यार्थी परिषद् राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गद्दारी बरदाश्त नहीं करेगी एवं गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर की तपोभूमि पर आतंकवाद की पाठशाला नहीं खोलने देगी।

राष्ट्रीय मंत्री रमाशंकर सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार एक आई.ए.एस. अधिकारी की सलाह पर देश की अस्मिता, सुरक्षा को ताक पर रखकर निर्णय ले रहे है एवं बिहार को अपनी जागीर समझने की भूल कर रहे हैं। किशनगंज भारत-बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण चिकेन नेक पट्टी पर विदेशी विध्वंसकारी संस्थाओं के निशाने पर है। वे अपने एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में किशनगंज जिले का प्रयोग करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं आई.एस.आई. के इशारे पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में खोलने के निर्णय को अमलीजामा पहना रही है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक बिहार सरकार ए.एम.यू. की शाखा खोलने के निर्णय को वापस नहीं लेगी तब तक विद्यार्थी परिषद् का आन्दोलन निरंतर जारी रहेगा।

प्रदेश अध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार ने कहा कि ए.एम.यू. के संविधान में विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित मस्जिद से 25 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत ही शोध केन्द्र, पत्राचार पाठ्यक्रम, उपशाखा खोलने का प्रावधान है परंतु सरकार इस नियम का उल्लंघन करते हुए हजारों किलोमीटर दूर किशनगंज में शाखा खोलने का निर्णय ले रही है एवं देश में दंगा फैलाने वाले, विश्वविद्यालय कैम्पस में राष्ट्रध्वज जलाने वाले, सिमी (SIMI) जैसे आतंकवादी छात्र संगठन की स्थापना करने वाले अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए किशनगंज जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिले में 250 एकड़ भूमि दी है।

प्रदेश मंत्री राजेश सिन्हा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर परिषद्-कार्यकर्ताओं का संवेदनशील होना स्वभाविक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में खुलने से आई.एस.आई., हुजी आदि राष्ट्रविरोधी संगठनों की शरणस्थली बन जायेगी। छात्रों को आई.एस.आई. द्वारा आर्थिक प्रलोभन देकर आतंकवादी दस्ते में शामिल होने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

प्रदेश सह संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा कि यदि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खुलेगी तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार के सीमावर्ती जिलों से ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में पृथक राष्ट्र की मांग उठेगी।

इस अवसर पर हिमांशु यादव, आदित्य कुमार, रौशन कुमार सिंह एवं अनिल ठाकुर आदि ने संबोधित किया। मंच संचालन विभाग संगठन मंत्री शिवशंकर सरकार ने किया।

■

यह स्वायत्तता नहीं गले की फांस है

■ अजय भारती

जम्मू कश्मीर एक बार फिर चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। कश्मीर घाटी में सरकार अपना नियंत्रण प्राय: खो चुकी है। अनियंत्रित भीड़ सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए सरकारी सम्पत्ति विशेषकर शासन की प्रतीक जैसे पुलिस स्टेशन और सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। प्रतिकार में गोली चलती है जिसमें जान-माल का नुकसान हो रहा है और गुस्से को हवा मिलती है। यह एक कभी न खत्म होने वाला कुचक्र बन गया है। समस्या इतना भीषण रूप धारण कर चुकी है कि सरकार बेबस और लाचार बनकर एकतरफा घोषणा कर रही है पर विघटन पर उतारू भीड़ सुनने को तैयार नहीं है। ब्लैकमेल की यह राजनीति देश की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता के लिए चुनौती बन गई है। स्पष्ट दिख रहा है कि मजहब के नाम, विशेषकर इस्लाम के नाम पर भारत का एक और विभाजन करने की तैयारी हो रही है। या यूं कहें कि निर्णय हो चुका है अब इस निर्णय को भारत की जनता के गले उतारने की कवायद चल रही है।

आतंकवाद अमान्य

दुनिया भर में आज आतंकवाद को कहीं पर भी खुलकर समर्थन नहीं मिल रहा। 11/9 को अमरीका पर हुए आतंकी हमले के पश्चात् तो वास्तव में आतंकवाद के विरूद्ध एक ऐसी जनभावना उत्पन्न हुई है कि चाह कर भी कोई देश या प्रभावी राजनैतिक विचार आतंकवाद को सही नहीं ठहरा पा रहा है। आतंकवाद की राजनीति के पूरक साधन के रूप में उपयोग करने वाले पाकिस्तान जैसे देश भी अपनी नीति को छिपकर लागू करने के लिए बाध्य हो गये हैं। बदली हुई इस परिस्थिति का प्रभाव स्वाभाविक रूप से घाटी पर भी पड़ा। निरंतर हिंसा तथा अलगाववादी नेताओं की दोहरी जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देख रही जनता ने अपना समर्थन इनसे वापस लिया। सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान के कारण हिंसा में काफी कमी आ गई। घाटी का मुस्लिम नौजवान भी भावनात्मक नारेबाजी को छोड़कर देश की आर्थिक विकास यात्रा का हिस्सा बनने की तैयारी का प्रदर्शन करने लगा। चुनाव में उत्साहवर्धक स्वैछिक भागीदारी इसी परिस्थिति का परिणाम था।

कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस का अवसरवादी गठजोड़

राज्य में विधानसभा के चुनाव नतीजे खंडित जनादेश के रूप में सामने आये। किसी भी राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। चुनावों से ठीक पहले पी.डी.पी. ने अमरनाथ यात्रा भूमि विवाद खड़ा करके गुलाम नबी आजाद की सरकार से समर्थन वापस लिया था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मुफ्ती सईद ने ने.का. को समाप्त करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाये थे। अपने जनाधार और पार्टी ढांचे को बचाने के लिए ने.का. को सरकार में रहना तथा पी.डी.पी. को सरकार से बाहर करना अति आवश्यक लग रहा था। इस परिस्थिति का पूरा-पूरा अवसरवादी लाभ कांग्रेस ने उठाने का पाप दोहराया। ने.का. डा. फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा लोगों से प्रचार के बीच कर चुकी थी। परन्तु कांग्रेस को एक कठपुतली चाहिए थी। राहुल-सचिन पायलट-उमर अबदुल्ला ध्रुवी ने डा. फारूक और ने.का. को पी.डी.पी. का डर दिखा कर उमर अबदुल्ला जैसे अनुभवहीन, अपरिपक्व तथा राजनैतिक दृष्टि से अक्षम, आधारहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया तथा देश की सुरक्षा एवं एकता को भी दांव पर लगाया। उमर के मुख्यमंत्री बनने के कारण ने.का. के वरिष्ठ नेताओं को नाराज एवं अलग-थलग कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के नाजुक पद पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों को निराश कर दिया और सुरक्षा बलों द्वारा परिश्रम और बलिदान से प्राप्त प्रत्येक लाभ को गंवाया। मुख्यमंत्री,

नेता प्रतिपक्ष तथा पृथकवादी नेता की भूमिका को एक साथ निभाने का विनाशकारी दुस्साहस करके उमर ने सबको सकते में डाल दिया। अगर वह कोई भूमिका निभाना भूल गये तो वो थी कमाण्ड के प्रमुख के नाते देश की सुरक्षा की।

आई.एस.आई. पृथकतावाद का पुनर्जन्म

लोगों के उत्साह भरी आशा को क्षुब्ध निराशा में बदलते देख आई.एस.आई. तथा अलगाववादियों को अपने मतान्ध विचार के लिए नये जीवन की झलक दिखाई दी। पी.डी.पी. को शासन से दूर रहना भा नहीं रहा था। अत: सबने मिलकर लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। डेढ़ से दो साल के समय में लोगों को एक बदली हुई रणनीति के अंतर्गत तथाकथित लोकतांत्रिक तरीके से विद्रोह के लिए तैयार किया गया। बच्चों, महिलाओं विद्यार्थियों को पत्थरबाजी के लिए प्रेरित करके योजना के अनुसार 'मासूमों' को सुरक्षा बलों के हाथों गोली चलाकर मारने का षड्यंत्र लागू होने लगा। ज्यों-ज्यों मरने वालों की संख्या बढ़ती गई त्यों-त्यों हालात और बिगड़ने का आधार बनता गया। हालात यह हो गये हैं कि पिछले कई महीनों से लगभग लगातार कर्फ्यू है। कर्फ्यू तोड़कर लोग निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। भारत में कामनवेल्थ गेम्स और नवम्बर मास में अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा को ध्यान में रखकर इन प्रदर्शनों में तेजी लाई जा रही है ताकि अन्तरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करके भारत सरकार को दबाव में लाया जाए। योजना के अन्तर्गत दिल्ली में गतिविधि को तेज करना भी आवश्यक है। अमरीकी दबाव में काम कर रही मनमोहन सिंह सरकार कश्मीर के मामले में झुकती हुई साफ दिखाई दे रही है। इसका सबसे खतरनाक पहलू है स्वायत्तता की पेशकश करना। घाटी में निरंकुश भीड़ जब अराजकता फैला रही हो, जिनके नारे 'निजामे मुस्तफा' और 'आजादी' हों, जब तथाकथित मुख्य धारा में शामिल दल लोगों की भीड़ का हिस्सा बन रहे हों और 'भारत से सहानुभूति' रखने वाले नेता पृथ्कतावादी भाषा में सुर से सुर मिला रहे हों ऐसे में राज्य से आये प्रतिनिधिमण्डल के समक्ष स्वायत्तता की बात करना कहां की समझदारी है, यह समझ से बाहर है।

स्वायत्तता देश के गले की फांस बनेगी

कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को देश से खिलवाड़ की आदत हो गई है। पं. नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस सदैव कश्मीर के मामले में मनमानी करने की छूट देकर राज्य के आम नागरिक को देश से दूर करने का मौका दे रही है। स्वायत्तता की मांग ने.कां. की मांग है। यह राज्य के लोगों की मांग नहीं है। इसका साधारण भाषा में अर्थ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद इत्यादि का जम्मू-कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। भारत की जनता को भी कोई हक नहीं होगा यह पूछने का कि उनकी खून-पसीने की कमाई को कश्मीर के नेताओं के ऐशोआराम पर क्यों खर्च किया जा रहा है। भारतीय सेना को अपने प्राण न्यौछावर करते रहना होगा बदले में 'उफ्फ' तक करने की इजाजत नहीं होगी। 1953 से पहले की परिस्थिति यानि 'परमिट सिस्टम' का पुन: लागू होना। वैष्णोदेवी या बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए एक प्रकार का पासपोर्ट चाहिए होगा। पर इस सब से खतरनाक पहलू है देश के शेष भाग पर इसका प्रभाव। इससे जो सन्देश स्पष्ट निकल रहा है वह यह है कि भारत की एकता, अखण्डता तथा सम्प्रभुता पर समझौता हो सकता है। यह संदेश कितने अलगाववादी आंदोलनों को बल प्रदान करेगा इसकी कल्पना सहज रूप से की जा सकती है।

एक और पहलू जो भारत को गृहयुद्ध की स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1947 में भारत का विभाजन करके मुस्लिम होमलैण्ड के नाम पर मुसलमान मतावलम्बियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक भूमि दी गई। अब इस्लाम के नाम पर पुन: विभाजन स्वीकारा गया तो देश में रह रहे शेष मुसलमान किस औचित्य से भारत में रह पायेंगे। क्या यह 'धर्म निरपेक्षता' को दफन नहीं करेगा। और मजहब के नाम पर पुन: एक बार खून की नदी बहाने का खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। क्या देश यह सब स्वीकार करेगा? ■

पं. दीनदयाल उपाध्याय

समर्पित जीवन

एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जा रहे थे। डिब्बे में एक लड़का आया और उन सज्जन के जूते उठाकर पालिश करने लगा। उसी डिब्बे में जिले के एक उच्च पदाधिकारी भी यात्रा कर रहे थे। पालिश करने के बाद वह लड़का उठा और अफसर से पूछने लगा- साहब पालिश।

साहब ने पूछा 'कपड़ा है साफ करने का' लड़के ने दीनता से कहा 'नहीं'। साहब ने कहा-तब जाओ। लड़का पैसे लेकर जाने लगा। चेहरे पर बेबसी की छाया थी। वे सज्जन उठे और उसे रोककर कहा 'बच्चे साहब के जूतों पर पालिश करो। फिर अपने झोले से एक पुराना तौलिया निकाला। उसका एक टुकड़ा फाड़ा और लड़के को देते हुए कहा- लो बच्चे, ये कपड़ा ले लो। ठीक से रखना, फेंकना नहीं। इसके बिना तुम्हारा अभी नुकसान हो गया था। हतप्रभ अधिकारी उनकी ओर देख ही रहे थे कि स्टेशन पर हजारों कार्यकर्ता उस व्यक्ति के समीप आकर नारे लगाने लगे- दीनदयाल उपाध्याय जिन्दाबाद। अधिकारी ने कहा-आप ही है आल इंडिया लीडर दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे थे पं. दीनदयाल उपाध्याय।

दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर 1916 को राजस्थान के धनकीया ग्राम में हुआ। 3 वर्ष से कम उम्र में उनके पिता भगवती प्रसाद एवं 8 वर्ष से कम उम्र में उनकी मां रामप्यारी देवी का स्वर्गवास हो गया। बाल्यकाल में माता-पिता की मृत्यु होने के बाद वे अपने नाना के घर आ गए।

पढ़ाई के लिए दीनदयाल को मामा राधारमण के साथ गंगापुर भेजा। गंगापुर में आगे पढ़ाई की व्यवस्था न होने से राजघर जाकर उन्होंने 8वीं व 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। हाईस्कूल में अध्ययन के लिए दीनदयाल राजघर से सीकर गये।

उन्हें मैट्रिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने पर सीकर महाराजा ने उन्हें स्वर्णपदक, पुस्तकों के लिए 250 रुपए एवं 10 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति व आर्शीवाद दिया। उनकी रेखा गणित की उत्तर पत्रिका काफी वर्षों तक सहेज कर रखी गई। 1931 में इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाकर स्वर्णपदक प्राप्त किया। अभी तक किसी विद्यार्थी ने इतने अधिक अंक प्राप्त नहीं किये थे। दीनदयाल जी बी.ए. के लिए पिलानी से कानपुर आये। 1937 में यहां उनका परिचय बलवंत महासिंघे एवं सुन्दर सिंह जी भंडारी से हुआ। इन्हीं के प्रयास से वे संघ कार्य में रुचि लेने लगे। इस बीच दीनदयाल जी का कानपुर के संघ शिक्षा वर्ग में जाना हुआ। वहां डा. हेडगेवारजी से बातचीत कर अपना जीवन देश को समर्पित करने का निर्णय किया। और संघ के प्रचारक निकले।

महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर शासन ने संघ पर प्रतिबंध लगाया। उस समय दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश के प्रांत सहप्रचारक थे।

दीनदयाल जी ने राष्ट्रधर्म प्रकाशन नाम से संस्था स्थापित की। अपने विचारों के प्रसार के लिए राष्ट्रधर्म मासिक, पाञ्चजन्य साप्ताहिक, स्वदेश नामक दैनिक प्रारंभ किये। इन्हें प्रारंभ कर चलाने में सम्पादक, कम्पोजीटर, पत्रिकाओं को ले जाने वाला भारवाहक तथा कार्यालय के चपरासी का भी काम उन्होंने किया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्तूबर 1951 में

भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी प्रामाणिक व उत्तम कार्यकर्ताओं के सहयोग हेतु संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी से मिले। गुरुजी ने श्री दीनदयाल को जनसंघ के लिए दिया।

1952 में कानपुर में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। उसमें श्यामाप्रसाद मुखर्जी दल के अध्यक्ष एवं दीनदयाल उपाध्याय को दल के महामंत्री के नाते नियुक्त किया। अधिवेशन में मुखर्जी ने गर्व से घोषणा की, इनके जैसे और दो दीनदयाल मिल गये, तो मैं देश के सारे राजकीय मानचित्र को बदल दूंगा। कश्मीर आन्दोलन का सारा दायित्व दीनदयाल को सौंपा गया। डा. मुखर्जी ने सत्याग्रहियों के साथ कश्मीर में प्रवेश किया। वे पकड़े गये। श्रीनगर के कारागार में सन्देहास्पद स्थिति में उनका स्वर्गवास हुआ।

शैशव अवस्था में जनसंघ को बड़ा आघात पहुंचा। अपरिमित शोकग्रस्त होते हुए भी उन्होंने जनसंघ को सुदृढ़ करने का निश्चय किया। 1953 से 1967 लगभग 15 वर्ष तक दल के महामंत्री के रूप में काम कर उस कोमल अंकुर को वट वृक्ष के रूप में विकसित किया।

स्वयं अध्ययन व चिन्तन कर एकात्मक मानववाद जैसा समग्र चिन्तन विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। भारतीय चिन्तन कहता है कि व्यक्ति और समाज न बांटी जा सकने वाली इकाई है। इसको आप बांट नहीं सकते। व्यक्ति और समाज जब बंट जाता है तो मानव मर जाता है, मानव रहता ही नहीं। दीनदयाल जी ने कहा, भारत की मनीषा के अनुसार समग्रता और सम्पूर्णता से देखो तो पाओगे कि मानव में व्यष्टि और समष्टि की एकात्मता है। दीनदयाल जी ने कहा भारत का संदर्भ उससे आगे है, व्यष्टि-समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। इनमें भी एकात्मता है। इसलिए यह एकात्मता का विचार, यदि मानव के सुख का संधान करना है तो इस एकात्मकता के विचार को समझना होगा। इस एकात्मता के विचार को समझते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमें केवल व्यक्ति के सुख की साधना नहीं करनी है। यदि हमने समाज को व्यक्तिवादी बनाया तो सुख की लूट मच जायेगी और कोई सुखी नहीं हो पाएगा और यदि हमने समाज के नाम पर व्यक्ति की अस्मिता को नकार दिया तो भारत नौकरों का देश बन जायेगा।

एकात्मता का विचार, यदि मानव के सुख का संधान करना है तो इस एकात्मकता के विचार को समझना होगा। इस एकात्मता के विचार को समझते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमें केवल व्यक्ति के सुख की साधना नहीं करनी है। यदि हमने समाज को व्यक्तिवादी बनाया तो सुख की लूट मच जायेगी और कोई सुखी नहीं हो पाएगा और यदि हमने समाज के नाम पर व्यक्ति की अस्मिता को नकार दिया तो भारत नौकरों का देश बन जायेगा।

दिसम्बर 1962 में केरल के कालीकट अधिवेशन में पं. दीनदयाल जी जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने। 11 फरवरी 1968 को रात्रि की रेलगाड़ी से दीनदयाल जी लखनऊ जा रहे थे। दूसरे दिन मुगलसराय पर दीनदयाल जी का कपड़ों में लिपटा शव देखा गया।

अटल जी ने कहा सूर्य छुप गया अब हमें तारों के प्रकाश में मार्ग ढूंढना होगा।

इंदिरा जी ने कहा यद्यपि हमारे विचार आपस में नहीं मिलते थे परन्तु वह एक नैतिक नेता थे जिनके असामयिक मृत्यु से देश को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

दीनदयाल जी मात्र 42 वर्ष जीवित रहे परन्तु उनके जीवन की सुगंध सैकड़ों वर्षों तक रहने वाली है। ■

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति प्रमुख हैं।)

दस्तावेज

केवल चेहरे नहीं सत्ता का चरित्र बदलो

त्रिमूर्ति पद छोड़े

श्री जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर को एक पत्र लिखकर 'वर्तमान गम्भीर स्थिति' पर चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि तीस वर्षों के बाद आज हमें दोबारा यह मौका जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मिला है और इस अवसर को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अथवा आग्रह के कारण खो देना एक प्रकार से जनता के साथ धोखा होगा।

श्री नारायण ने कहा, 'हम छोटी-छोटी बातों में उलझे रहे और 1977 में नयी सरकार बनने पर जनता के मन में जो आशा पिफर से जगी थी, उसे पूरा नहीं कर पाये, तो देश में तानाशाही प्रवृत्तियों और ताकतों के पुनः उभरने का भी खतरा है। इसलिए देश के पुनर्जीवन का माध्यम बनने का जो गौरवपूर्ण अवसर जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हमें अपने को सि(करना चाहिए।'

उन्होंने सुझाव दिया है कि पिछले जनआन्दोलन में जो बहुत से नये लोग आये और खासकर, वैसे युवक-युवतियां, जिन का तत्कालीन किसी दल से सम्बंध नहीं था। उन्हें राजनैतिक प्रवाह में दाखिल करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

उन्होंने कहा है कि राजनैतिक जीवन में नया खून आता रहे, ताकि हम हमेशा ताजा रहे, इसके लिए युवाशक्ति को प्रयत्नपूर्वक आगे लाना और पुराने लोगों का पदों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मार्गदर्शन की भूमिका अदा करना आवश्यक है।

श्री नारायण ने अपने पत्र में जनता पार्टी के तीन नेताओं सर्वश्री मोरारजी देसाई, चरणसिंह और जगजीवनराम की प्रशंसा की है और कहा है कि इन लोगों ने जो कुछ कार्य किये हैं, वे किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया है कि मैं चाहता हूं कि ये लोग स्वेच्छा से पद त्याग कर पार्टी और सरकार का मार्गदर्शन करें।

इस बात को नजरअन्दाज करना भी ठीक नहीं होगा कि लोकसभा के चुनावों के समय जनता में जो उत्साह और आशा का संचार हुआ था, वह कुल मिलाकर ठण्डा पड़ गया है और जनता में निराशा की भावना बढ़ रही है। इसकी तह में हमें जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है कि 'जनता के कष्ट दूर करने के लिए कार्यक्रमों का अपना महत्व तो है ही, पर बुनियादी बातों के बारे में पहले स्पष्ट हो जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि जनतंत्र को मजबूत बनाने और उसका सपफलतापूर्वक संचालन करने के लिए यह आवश्यक है कि केवल चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासनिक तंत्र का आधार न रखकर उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सारी प्रक्रिया में शामिल किया जाये।'

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि एक ओर जनता तथा दूसरी ओर उसके प्रतिनिधियों तथा प्रशासनतंत्र के बीच की दूरी यथासम्भव कम हो। जनतंत्र में आज जनता की आस्था बढ़ाने के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक तथा सार्वजनिक जीवन में सादगी और मितव्ययिता लायी जाये तथा आडम्बर और पिफजूलखर्ची को रोका जाये। *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति जून, 1978)*

श्रद्धांजलि

श्री रामकृष्ण मिश्र

1963 से 1966 तक अभाविप के महामंत्री रहे श्री रामकृष्ण मिश्र। आपने इलाहाबाद में अभाविप के अन्दर काम शुरू किया। अभाविप उस समय देश का सर्वाधिक शक्तिशाली केन्द्र हुआ करता था। उसके प्रमुख कार्यकर्ता के नाते आपकी पहचान थी। अभाविप का केन्द्रीय कार्यालय में उस समय इलाहाबाद में था।

उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परमपूजनीय रज्जू भैया एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी के सम्पर्क में आने से आप अभाविप व संघ से जुड़े। वे बहुत समर्पित और संघनिष्ठ कार्यकर्ता थे। वे 80 वर्ष की आयु के थे। अभाविप के पश्चात् और किसान संघ में सक्रिय रहे। मूलतः आप कृषक थे। दो बार आप लोकसभा (1998-1999) के प्रत्याशी रहे। आप चन्द्रशेखर के सामने चुनाव लड़े। अभाविप की ओर से दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते है।■

साहित्य

हिन्दी की शताब्दियां

■ आशुतोष

फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर हिन्दी के एक बड़े साहित्यकार थे। पहले वाक्य में उन्होंने मेरे हाल ही में लिखे गये एक लेख की प्रशंसा की। मेरे लिए यह प्रशंसा किसी पुरस्कार से कम न थी। लेकिन दूसरे ही वाक्य में मेरा उत्साह भंग हो चुका था।

उन्होंने प्रश्न किया-'यह जनसैलाब कौन सी भाषा का शब्द है'। मैं समझ गया कि आगे की बात किस ओर बढ़ने वाली है। संस्कृत के 'जन' शब्द को फारसी के 'सैलाब' के साथ जोड़ कर इस शब्द का जन्म हुआ है। सरल बनाने के नाम पर भाषा भ्रष्ट करने को आतुर अनेक विद्वान इसे सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम भी इससे प्रभावित हो, यह जानकर कष्ट हुआ। उन्होंने चोट की।

'जनसैलाब शब्द का आविष्कार मैंने नहीं किया। यह सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला शब्द बन चुका है। यह अर्थ देने वाला कोई शब्द हिन्दी में अगर है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है'-मैंने कहा।

तुम्हारी शब्दसामर्थ्य कम है यह किसका दोष है। यदि दोष है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे अज्ञान की पीड़ा को भाषा क्यों सहन करे? तुम्हारी जानकारी के लिए, इसके स्थान पर जनमेदिनी, जनज्वार या जनपारावार शब्द का उपयोग भी किया जा सकता था।

'ओह! यह शब्द बहुत कठिन हैं, पाठक के लिए इन्हें समझना मुश्किल है'।

'जो पाठक सैलाब समझ सकता है वह ज्वार क्यों नहीं समझेगा'? वे बोले।

आप बड़े साहित्यकार हैं इसलिए इन कठिन साहित्यिक शब्दों के पीछे पड़े हैं। आज-कल की पत्रकारिता में यह भाषा नहीं चलती है। पत्रकारिता के संस्थानों में भी पढ़ाया जाता है कि भाषा ऐसी हो जो सबकी समझ में आये। इसके लिए हिन्दी शब्दों के प्रयोग का दुराग्रह त्यागकर वैकल्पिक उर्दू-फारसी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करने में कोई दोष नहीं। एक बड़े हिन्दी दैनिक के आज के ही अंक में प्रथम पृष्ठ पर चिपके ताजमहल के चित्र के नीचे आपने नहीं पढ़ा-'ताज के धवल हुस्न को निहारता टूरिस्ट'। सवाल भाषा का नहीं 'कम्युनिकेशन' का है।

इसका अर्थ है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में संवाद होता ही नहीं था। सिंधु तट का तीर्थयात्री कन्याकुमारी पहुंच कर भी अपनी बात लोगों को समझा सकता था। शंकराचार्य धुर दक्षिण से चलकर काशी के ब्राह्मणों को अपनी बात समझा सकते हैं लेकिन आज के पत्रकार को स्थानीय पाठक को भी अपनी बात समझाने के लिए विदेशी शब्दों का सहारा चाहिए।

आप साहित्यकारों की समस्या यही है। तुरंत शंकराचार्य के युग में पहुंच जाते हैं। आज का सामना करने के बजाय इतिहास में जीने से क्या हासिल होगा। अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है। टेक्नॉलॉजी ने दुनियां को एक गांव में बदल दिया है। अंग्रेजी अब सारी दुनिया की भाषा बन चुकी है। अगर उसके शब्द हमारी भाषा में भी हैं तो इसमें गलत क्या है। नई जनरेशन आपकी साहित्यिक भाषा नहीं जानती, पढ़ती भी नहीं। उसे एक ऐसी भाषा चाहिए जिसे हर कोई समझ सके। वही अखबार की भाषा है।

इसीलिए आज समाचार पत्रों की हालत यह हो गई है कि उसके पाठक कम हैं और दर्शक अधिक। देश में सबसे अधिक पाठकों का दावा करने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र को मेरा पीएचडी बेटा भी दस मिनट में पढ़ डालता है और मेरा अनपढ़ नौकर रामू भी उसके पृष्ठों को दस मिनट तक निहारता रहता है।

आप बेकार ही अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। आज हर नौजवान अंग्रेजी में बात करना चाहता है, सीखना चाहता है। ज्यादातर तो इन अंग्रेजी अखबारों को पढ़ कर ही अपनी अंग्रेजी 'इंप्रूव' करते हैं।

'लेकिन वह इससे कैसे सीख सकेंगे, जब अंग्रेजी पत्रकार भी तुम हिन्दी पत्रकारों की तरह ही अन्य भाषाओं के शब्दों के बिना 'कम्यूनिकेशन' पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह 'मॉडस ऑपरेन्डी', 'लोकस स्टैंडाई'

और 'करीकुलम वाइटे' तो अंग्रेजी शब्द नहीं हैं। फिर वे इन्हें क्यों बार-बार प्रयोग करते हैं।' उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।

'यह शब्द तो अब हिन्दी पत्रकारिता में भी आ चुके हैं। लोग इन्हें अपना भी रहे हैं। नये शब्दों को जोड़ने से हिन्दी की शब्दावली भी बढ़ेगी और उसकी स्वीकार्यता भी'। मैंने कहा।

'हिन्दी किसी स्वीकार्यता की मुहताज नहीं है। यह शताब्दियों से भारत में अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। आज भी है, आगे भी रहेगी। इसकी वैज्ञानिकता के आगे तुम्हारी उर्दू कहीं नहीं ठहरती। अंग्रेजी भी नहीं। मिलावटी भाषा तो बिल्कुल भी नहीं।' वे और उग्र होते हुए बोले।

'आप फिर वहीं पहुंच गये। बात हिन्दी के सैद्धांतिक समर्थन की नहीं है। बात है 'कम्युनिकेशन' की, जो अंग्रेजी के शब्द डाले बिना मुश्किल है। आज नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चे भी अंग्रेजी की 'पोयम' कितने 'कान्फीडेंस' से सुनाते हैं। अगर उन्हें आपके जमाने के पहाड़े सुनाने को कह दिया जाये तो वे बगलें झांकने लगेंगे। जिन्हें हिन्दी की गिनती नहीं आती उन्हें अगर आप 'जनज्वार' जैसे शब्द पढ़ायेंगे तो वे क्या समझेंगे।' मैंने भी हार न मानने की कसम खा ली थी।

'क्यों! अगर वे अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़कर अंग्रेजी सीख सकते हैं तो हिन्दी का समाचार पत्र पढ़कर हिन्दी क्यों नहीं। क्या तुमने उन नब्बे प्रतिशत भारतीयों के बारे में कभी सोचा है जिनका सामना आज तक अंग्रेजी की वर्णमाला से नहीं हुआ। वे हिन्दी अथवा अपनी मातृभाषा में ही संवाद करते हैं और पूरे भारत का तीर्थाटन बड़ी सहजता से कर लेते हैं'।

'अगर तुम्हें और तुम्हारे पत्रकार शिरोमणियों को लगता है कि अंग्रेजी के शब्द डाले बिना भाषा की संप्रेषणीयता खतरे में पड़ जायेगी तो यह भ्रम है। हिन्दी समाचार पत्र को तुम लोगों ने आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि बिना अंग्रेजी में स्नातक किये हिन्दी के समाचार पत्र को समझ पाना कठिन हो गया है। तुम पाठक को अंग्रेजी से जोड़ नहीं रहे हो बल्कि समाचारों से दूर कर रहे हो'।

मेरे लम्बे मौन ने उन्हें संयत होने का अवसर दिया। अब उनका स्वर ऐसे अभिभावक का लग रहा था जो अपनी संतान के आचरण पर सचमुच दुखी हो। समझाने के स्वर में उन्होंने कहा-'किसी समाज से उसकी भाषा छीन लेना और विदेशी शब्दों को निगलने के लिए विवश करना किसी औपनिवेशिक तंत्र की कार्यप्रणाली तो हो सकती है, स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र की नहीं। इस तरह से तुम इस देश के नागरिकों को समाचारों से नहीं बल्कि सरोकारों से दूर कर रहे हो। इस तरह तुम बाजार का विश्वास तो पा लोगे लेकिन देश के साथ विश्वासघात करके'।

'भारत की कालगणना वर्षों में नहीं, युगों में मापी जाती है। उसे लम्बी यात्रा करनी है जो उधार की बैसाखियों भरोसे नहीं की जा सकती। उसे अपने पांवों पर ही आगे बढ़ने दो। अगर तुम्हारे यह टोटके बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकते तो इन्हें यहीं छोड़ दो। एक बार लगेगा कि पांव कांप रहे हैं लेकिन मन का विश्वास पक्का हो तो पांव तो आगे बढ़ेंगे ही। हिन्दी दिवस नहीं, हिन्दी की शताब्दियां भावी इतिहास लिखने को उद्यत हैं'। ■

एक्लव्य 2010 का कार्यक्रम चेन्नै में सम्पन्न

एक्लव्य 2010 पुरस्कार वितरण समारोह में स्वागत भाषण श्री बाला जी वेणुगोपाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. जी विश्वनाथन वाईस चांसलर विट युनिवर्सिटी वेल्लूर (तमिलनाडु) अध्यक्षीय भाषण डॉ. एस. सुब्बैया और तकनीकी परिप्रेक्ष्य में छात्रों की भावी सम्भावनाओं पर श्री एस. गिरीधरन चेयरमैन, ई.डी.एस.ई.आर.बी. ने अपने विचार व्यक्त किए। अभाविप के बारे में विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री के.एन. रघुनन्दन ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रकट किए। और धन्यवाद भाषण श्री पी. सुमुगराजा ने दिया। ■

असम विश्वविद्यालय पर अभाविप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

अभाविप की सिल्चर ईकाई में कार्यकर्ताओं ने 22 जुलाई को आसाम विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष 9 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में प्रदर्शन किया। स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू करना, पुनर्मूल्यांकन की फीस कम करना, आधारभूत सुविधाओं का विकास और विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जांच बिठाये जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इन मांगों के समर्थन में 2000 से अधिक छात्र पहुंचे। जिसमें 20 कालेजों के छात्र कार्यकर्ता बैनर लेकर आये थे। छात्रों की रैली का नेतृत्व प्रांत संगठन मंत्री मनोज निखरा, रूपम दत्ता, जय बेनिक, मनोज दास, आलोक गुप्ता व अन्य लोग कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रनेताओ के प्रतिनिधि मंडल से बात की। इस दौरान पूरा विश्वविद्यालय परिसर छावनी बना रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। ■

तिरुअनन्तपुरम् में कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

अभाविप के द्वारा 11 अगस्त को सचिवालय के सम्मुख तिरुअनन्तपुरम् में पीडीपी नेता व बंगलोर बम धमाके में आरोपी नासिर मोहम्मद मदनी की गिरफ्तारी एवं पापुलर फ्रंट आफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के समूह पर पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उसके पश्चात् पुलिस की जोर जबरदस्ती के कारण छात्रों और पुलिस में झड़प हुई जिसमें 9 परिषद् कार्यकर्ता घायल हुए। घायलों को पुलिस ने काफी देर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। बाद में परिषद् कार्यकर्ताओं के रोष को देखते हुए उन्हें मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभाविप के प्रांत मंत्री जी.एम. महेश एवं सह मंत्री एन.पी. शिखा ने कहा सरकार छात्रों पर आंसू गैस के गोले, वाटर केनन और लाठियां बरसा रही है। आतंकवादी को सरकारी मेहमान बनाया हुआ है। इसके विरोध में अभाविप ने पूरे केरल प्रांत में शैक्षणिक बंद का आह्वान किया।

■

पटना में पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन

पटना, 9 जुलाई 2010

अभाविप ही एकमात्र छात्र संगठन है जहां कार्यकर्त्ता उच्च आदर्शों के साथ जीवन जीने की पद्धति सीखते है। इस परंपरा को बनाये रखने के लिए सैकड़ों पूर्णकालिक कार्यकर्ता ने घर छोड़कर आने वाले पीढ़ी को चरित्र निर्माण एवं पढ़ाई के साथ लड़ाई करने लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। उक्त बातें अभाविप पटना महानगर इकाई द्वारा आयोजित नुतन-पुरातन कार्यकर्त्ता मिलन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कही। उन्होनें परिषद् द्वारा झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित श्रमानुभव शिविर की याद को ताजा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण जीवन पद्धति का दर्शन कराने काम किया जाता है। अपने 60 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में अपने कार्यक्रम के द्वारा समाज में सर्वस्पर्शी कार्य के तहत सभी समुदाय को संगठन से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होने कहा कि बिहार विद्यार्थी परिषद् द्वारा सर्वाधिक रक्तदान करने वाले संगठन के रूप में कई बार पुरस्कृत किया गया है। हम लोग अपने समय में जिस सपने को सकार नहीं कर पाये थे उसे वर्तमान पीढ़ी के कार्यकर्त्ता पूरा कर रहे है जो सराहनीय है। आज संगठन के कार्य सर्वस्पर्शी एवं प्रभावी होने के कारण समाज का विश्वास को जीतने में कामयाब हुई है एवं विद्यार्थी परिषद् किसी मुद्दों पर अपनी मांग एवं सुझाव देती है तो प्रशासन एवं सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करती है।

मिलन समारोह में बाएं से श्री दिनेश कुमार, क्षेत्र संगठन मंत्री, श्री उमेश, प्रदेश अध्यक्ष, श्री सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री बिहार एवं श्री हरेन्द्र प्रताप

परिषद् के पूर्व महामंत्री श्री हरेन्द्र प्रताप ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने वाला एक मात्र छात्र संगठन है। राजसत्ता जब भ्रष्ट एवं निरंकुश होती है तो छात्रशक्ति का दायित्व उस पर अंकुश लगाने का है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में कार्य करने के वाद कार्यकर्त्ता राजनीति में जाते है तो उनके पांव भ्रष्टाचार के दलदल में फंस सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कार्यकर्त्ता को उनका विरोध करके अंकुश लगाने का दायित्व है। अपने इस कर्त्तव्य से विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्त्ता को पीछे नहीं हटना चाहिए।

श्री प्रताप ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी एवं गैसरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के चरित्र निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है परंतु विद्यार्थी परिषद् व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। विदेशी विचारों को श्रेष्ठ मानकर हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भारत का जीवन दर्शन सर्वश्रेष्ठ है इसे नहीं भूलना चाहिए। भारत में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों पर उपलब्धिपूर्ण कार्यों पर अनुसंधान एवं शोध के कार्य नहीं हुए है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के तारेगना में प्राचीन खगोलविद् आर्यभट्ट द्वारा शोध किया गया परंतु आजादी के छह दशक के बाद भी तारेगना पर शोधकार्य क्यों नहीं हुआ यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रदेश अध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार ने कहा कि जब

बिहार की धरती नक्सलवाद एवं नरसंहार की आग में झुलस रहा था एवं समाज के एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के खून को प्यासे होकर समाज को रक्तरंजित करने पर तुले थे तो विद्यार्थी परिषद् अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जहानाबाद में नरसंहार से प्रभावित गांवों में शांति मार्च के माध्यम से समाज में आपसी सदभाव एवं भाईचारा स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया।

इस अवसर पर परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुमार ने विद्यार्थी परिषद् द्वारा 2008 कोशी त्रासदी के समय चलाये गये सेवा कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टिकरण एवं वोट की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। छात्रशक्ति इसका जवाब देने के लिए जागृत हो चुका है। सीमांत पटेल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् राष्ट्रीय आपदा के समय पीड़ितों की सहायता कर उसके दु:ख-दर्द को बांटने का कार्य किया है। मंच संचालन प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पप्पु वर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन छात्रा प्रमुख पुष्पांजली ने किया। ■

श्रद्धाञ्जलि

डा. सुरेन्द्रनाथ मित्तल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता डा. सुरेन्द्रनाथ मित्तल का फरीदाबाद में गत 21 अगस्त को सायं 5.00 बजे 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1924 में जन्मे सुरेन्द्र जी 1941 में ग्वालियर में स्वयंसेवक बने, 1945 में प्रयाग विश्वविद्यालय से राजनीतिशास्त्र में एम.ए. करके संघ के प्रचारक निकले। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर, सुल्तानपुर और रामपुर आदि जिलों में कार्यरत रहे। गांधीजी की हत्या के बाद छह माह सुल्तानपुर जेल में और 1975-77 में आपात्काल में उन्नीस महीने इलाहाबाद जेल में बन्दी रहे। 1948 में हिन्दुस्थान समाचार के लखनऊ केन्द्र के प्रमुख रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। आप 1955-56 में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। प्रचारक जीवन से लौटकर प्रयाग विश्वविद्यालय से 'समाज और राज्य: भारतीय विचार' विषय पर डाक्टरेट की उपाधि अर्जित की। हिन्दी में पहला शोध प्रबन्ध लिखने का आग्रह किया। 1960 से 1984 तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1984 में 'रीडर' पद से सेवानिवृत्त हुए। 1962 में नवल पालकर द्वारा रचित 'डा. हेडगेवार' पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशक रहे। 1967-68 दो वर्ष प्रयाग से राष्ट्रधर्म मासिक का सम्पादन किया। डा. गोविन्द चन्द्र पांडे और डा. डी.पी. चट्टोपाध्याय के 'सेंटर फार स्टडीज इन सिविलाईजेशन' के द्वारा 2000 में 'कौटिल्य अर्थशास्त्र रिविजिटेड' ग्रंथ प्रकाशित किया। उन्होंने स्मृतियों, नीतिग्रंथों, पुराणों एवं महाभारत का गहन अध्ययन कर अनेक शोध निबंध देश-विदेश की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किये। विगत पांच वर्षों से वे अस्वस्थ चल रहे थे और गत एक वर्ष से स्मृतिलोप का शिकार थे। वे अपने पीछे तीन पुत्रियां और एक पुत्र छोड़ गये हैं। स्वभाषा और स्वदेशी वेषभूषा के प्रति अपना आग्रह उन्होंने जीवन भर निभाया।

■

अभाविप के 61वें स्थापना दिवस पर

मेरठ में मोटर साइकिल रैली

रैली में उत्साहित छात्र

9 जुलाई, मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ महानगर में विद्यार्थी परिषद् के 61वें स्थापना दिवस पर विशाल मोटर-साईकिल रैली निकाली गई।

9 जुलाई सुबह 10.30 बजे सूरजकुंड स्थित विद्यार्थी परिषद् कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थी परिषद् क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने रैली को रवाना किया। रैली का नेतृत्व तकनीकी प्रकोष्ठ प्रदेश प्रमुख अंकुर राणा ने किया। रैली कार्यालय से रवाना होकर बच्चा पार्क पहुंची। इस रैली में 250 बाइकें व आगे सजी-धजी जीप गाड़ी चल रही थी। रैली बेगमपुल पहुंची तो पुलिस प्रशासन ने रैली को रोकना चाहा परन्तु छात्रों की अधिक संख्या और आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा और रैली पी.एल. शर्मा रोड, कचहरी पुल, मेरठ कालेज कमीशनरी चौपला, पुलिस लाइन, फूलबाग चौराहा, गांधी आश्रम विश्व विद्यालय से होते हुए सर छोटू राम इन्जिनियरिंग कालेज पहुंची। रैली ने लगभग 25 कि.मी. की यात्रा तय की।

रैली का समापन चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. के. काक ने किया। प्रो. काक ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद् को देखने से एहसास होता है कि विद्यार्थी परिषद् छात्रहित के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी विश्वास रखता है। मेरा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से विद्यार्थी परिषद् के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा। विद्यार्थी परिषद् जो भी लड़ाई छात्रहित के लिए लड़ती है वह पूरे तथ्यों के साथ लड़ती है और समाधान अवश्य निकाल लेती है। बाद में प्रो. एस.के. काक ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया।

■

रैली का विहंगम दृश्य

प्रान्तीय छात्र नेता सम्मेलन सम्पन्न

7 सितंबर 2010, भागलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा प्रान्तीय छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के दिनकर भवन में किया गया। छात्र नेता सम्मेलन का उद्घाटन विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद् ही एक ऐसा छात्र संगठन है, जो सम्पूर्ण देश में छात्रों का नेतृत्व कर रहा है। देश एवं समाज में कोई भी समस्या आती है तो विद्यार्थी परिषद् सर्वप्रथम उसके लिए आवाज उठाती है तथा अंजाम तक पहुंचाती है।

श्री शर्मा ने कहा कि आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं अमरीका के दबाव के कारण देश के अन्दर शिक्षा का व्यापारीकरण काफी तेजी से हो रहा है। आज के. जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा में बाजारवाद हावी हो रहा है। जिसके कारण उच्च शिक्षा से गरीब एवं मेधावी छात्र वंचित हो रहे हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण के कारण आज देश के अन्दर आम छात्र अपने आपको शिक्षा से वंचित समझ रहे है। द्वापर युग में कृष्ण एवं सुदामा ने एक साथ शिक्षा ग्रहण कर अदभुत मित्रता की मिसाल पेश की। वहीं आज केन्द्र सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में आंख मूंदकर शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दे रही है। एक समय था जब भारत में शिक्षा दान की वस्तु हुआ करती थी लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा आज बाजार की वस्तु बनकर रह गई है। शिक्षा के विकास पर भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.5 प्रतिशत खर्च होता है। लेकिन यहां के मानव संसाधन मंत्री सिर्फ बयान जारी कर कहते है कि शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन तो हो नहीं रहा है बदले में यहां विदेशी विश्वविद्यालय की शाखा खोली जा रही है।

अगले दिन राष्ट्रीय मंत्री रामाशंकर सिन्हा ने शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ बोलते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ जिस प्रकार जबरदस्त आन्दोलन बिहार में हुआ ठीक उसी प्रकार शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ आन्दोलन का शंखनाद बिहार की धरती से किया जायेगा। आने वाले समय में शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ जन आन्दोलन शुरू करेंगे जिसका मुख्य नारा होगा 'शिक्षा में संस्कार चाहिए एवं जीने के लिए रोजगार चाहिए'।

प्रान्तीय छात्र नेता सम्मेलन में राज्य सरकार की शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति की तीव्र भर्त्सना करते हुए आम छात्र एवं समाज से शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने हेतु सशक्त जन आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया है। साथ ही प्रदेश में शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने हेतु राज्य सरकार से निम्न मांग की है-

1. प्रदेश के सभी निजी, सरकारी शिक्षण संस्थानों में शुल्क नियंत्रण एवं निर्धारण हेतु एक नियामक प्राधिकार बनाया जाय।
2. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं मानित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों पर नियंत्रण एवं इनकी मान्यता जांच हेतु सशक्त कानून बनाया जाय।
3. सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में की गयी शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाय।
4. कोचिंग संस्थानों में शुल्क निर्धारण हेतु समिति बनायी जाय।
5. निजी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो एवं डिग्री बेचने के धंधे पर पूर्णत: रोक लगाया जाय।
6. शिक्षा के व्यापारीकरण (KG To PG) को अविलम्ब समाप्त किया जाय।

■

एबीवीपी ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधि मंडल ने 22 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को चण्डीगढ़ में उनके निवास पर सौंपा।

मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए प्रदेश मंत्री विक्रम कोका ने कहा कि हरियाणा सरकार की गलत शिक्षा नीतियों के कारण आज प्रदेशभर का छात्र बुरी तरह परेशान है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गरीब छात्रों के लिए आधा दर्जन से भी कम सरकारी कालेज खोले है, लेकिन प्राइवेट कालेजों का आंकड़ा नौ सौ को पार कर चुका है। इन सभी प्राइवेट कालेजों में मोटी फीस है, जिसे देने में आम छात्र असमर्थ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लेने पर शिक्षा के व्यापारीकरण नहीं होने की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया है। जिसके खिलाफ प्रदेश इकाई ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया।

प्रतिनिधिमंडल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र नेता सुभाष कलसाना, प्रदेश मंत्री विक्रम कोका, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीनिवास, कृष्ण पांचाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरुण चौधरी, प्रवीन मेहता और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश वशिष्ठ थे।

सुरक्षा की मांग को लेकर उमड़ा छात्राओं का समुदाय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैम्पस में छात्राओं के प्रति बढ़ते असुरक्षित वातावरण व यौन शोषण की घटनाओं के विरोध में छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति ईरानी (अभिनेत्री) उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि, छात्राओं को कालेज कैम्पस में सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। देश को सशक्त बनाना है तो छात्राओं का सशक्तीकरण होना आवश्यक है।

मुख्य वक्ता डा. पायल मग्गो (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अ. भा.वि.प.) ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की इस वर्ष लगभग 30,000 सदस्यता हुई जिसमें छात्राओं की सदस्यता 25 प्रतिशत है।

कार्यक्रम के उपरांत कैम्पस में रैली निकाली गई जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों की लगभग 800 छात्राओं की सहभागिता रही तथा छः सूत्रीय खुला मांग-पत्र प्रशासन को सौंपा।

कार्यक्रम का मंच संचालन डुसू उपाध्यक्ष कृति वढेरा ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मनु कटारिया, श्रीमती वन्दना भगत, श्रीतेजा, शिल्पी, प्रिया डवास, नीतू, अपूर्वा आदि छात्र नेता उपस्थित रहे। ■

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा कश्मीर परिस्थिती पर जारी प्रेस वक्तव्य -

- कश्मीर में 11 जून से चल रहे हिसात्मक आन्दोलन की विद्यार्थी परिषद निन्दा करती है यह आन्दोलन स्वस्फूर्त न होकर अलगाववादियों की शह पर चलाया जा रहा आन्दोलन है। जिसे प्रत्यक्ष रुप से पीडीपी जैसे राजनैतिक दलों का समर्थन है।
- इस हिंसा में अभी तक 50 से ज्यादा लोग मारे गये हैं। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गयी है। लगभग 2000 सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजी में घायल हुये है।
- अलगाववादियों द्वारा युवकों को पत्थर फेंकने का प्रशिक्षण व पैसा दिया जा रहा है। यह एक नए प्रकार का आतंकवाद है।
- सिविल एरिया से सेना को हटा लिया गया है। सीआरपीएफ को ज्यादा अधिकार नही है।
- मुख्यमंत्री उमर के द्वारा कई बार अलगाववादियों की भाषा बोलने से उनके हौसले बढ़ गये हैं।
- अलगाववादियों को बार-बार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक पैकेज जिसमें अधिक स्वायत्ता जैसे मुद्दे है ऐसे का आश्वासन दिया जा रहा है।
- सगीर अहमदी रिपोर्ट को लागू करने की मांग है।
- पत्थरबाजों के पुनर्वास-रोजगार देने की बात हो रही है।
- पीओके में गये आतंकवादियों के वापस लौटने व समर्थन करने पर नरम व्यवस्था की बात की जा रही है।
- सुरक्षा बलों को हतोत्साहित किया जा रहा है। मुकदमें बना रहे है।
- कश्मीर के अलगाववादियों के साथ नक्सलियों का गठजोड़ उजागर हो रहा है।
- सुरक्षा बलों के स्पेशल पॉवर एक्ट को हटाने की बात हो रही है।
- अ.भा.वि.प. कश्मीर को राजनैतिक पैकेज के नाम पर अधिक स्वायत्तता देने व सुरक्षा बलों को अधिकारविहीन करने का विरोध करती है। परिषद का मानना है कि धारा 370 जैसी व्यवस्था के कारण आज कश्मीर में अलगाववादियों को बल मिला है और आज भी वहां दो संविधान और दो झंडे का प्रावधान है।
- परिषद मांग करती है कि अलगाववादियों द्वारा चलाये जा रहे इस आंदोलन को सख्ती से कुचला जाए तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों को अधिकार संपन्न बनाया जाये।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों से अपील करती है कि वह इस परिस्थितियों को देखते हुये आगे आये तथा केन्द्र सरकार पर लोकतांत्रिक दबाव बनाते हुए कश्मीर की परिस्थिति को ठीक करने में अपनी भूमिका निभाये। ■

चिदम्बरम का पुतला फूंका

केन्द्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम द्वारा कथित रूप से राष्ट्रीयता के प्रतीक भगवा रंग का अपमान किये जाने पर आक्रोशित अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा चिदम्बरम का पुतला फूंका गया। अभाविप के राज नारायण महाविद्यालय इकाई के अध्यक्ष नवीन कुमार एवं नगर सह मंत्री शैलेन्द्र कुमार के संयुक्त नेतृत्व में अतुल अब्राहम, राजन पासवान, छोटू, अविनाश, राजू, सुन्दरम, नीरज, राकेश कुमार समेत दर्जनों छात्रों के जत्थे ने पुतले के साथ शुक्रवार को नगर में प्रदर्शन किया। विभिन्न मार्गों से प्रदर्शन करते हुए छात्र गांधी चौक पर पहुंचे। सभा में तब्दील हो गया। जुलूस को संबोधित करते हुए उक्त छात्र नेताओं ने कहा कि भगवा राष्ट्रवाद का प्रतीक है। बावजूद इसके केन्द्रीय गृहमंत्री ने इसकी खिल्ली उड़ा समस्त देशवासियों को अपमानित किया है। अभाविप नेताओं ने यह भी कहा कि केन्द्र की कांग्रेस नीत सरकार द्वारा आतंकवाद को अपने नजरिये से देखा जा रहा है और इसे अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रवादी उन्हें आतंकवादी दिखाई देते है जबकि इस्लामिक आतंकवादियों के साथ कुटुम्ब की तरह व्यवहार किया जा रहा है। खूंखार आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने में किया जा रहा टालमटोल कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का ही परिणाम है। छात्रों द्वारा केन्द्र सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री का पुतला फूंक अपने रोष का इजहार किया गया। ■

स्मृति ईरानी का स्वागत करते हुए कार्यकर्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र सम्मेलन में रैली में छात्राएं

मैसूर विश्वविद्यालय में असंवैधानिक नियुक्तियों के विरोध में प्रदर्शन करते अभाविप के कार्यकर्ता

15 अगस्त को जम्मू में तिरंगा यात्रा निकालते अभाविप के कार्यकर्ता

बंगलोर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी नासिर मोहम्मद मदनी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर तिरुअनन्तपुरम् में प्रदर्शन करते अभाविप के कार्यकर्ता। वाटर केनन से कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करते पुलिस प्रशासन

हैदराबाद में परीक्षाओं में असफलताओं के विरोध में प्रदर्शन करते हुए छात्र कार्यकर्ता

आर.एन.आई. नं. 32464/78

लखनऊ में राष्ट्रीय छात्र नेता सम्मेलन को सम्बोधित करते राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री श्री कुमार सुनील मंचस्थ राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री श्री रवि कुमार एवं मांचली ठाकुर

मध्यप्रदेश के छात्र नेता सम्मेलन में दीप प्रज्ज्वल करते राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री के.एन. रघुनन्दन, राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा एवं कार्यक्रम में उपस्थित छात्र समुदाय

एकलव्य 2010 में उपस्थित अतिथि एवं पुरस्कृत छात्र समुदाय